

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE**Thursday, 25 July , 2024****Edition: International | Table of Contents**

Page 04 Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	मोदी ने कहा कि भारत यू.के. के साथ एफटीए के लिए प्रतिबद्ध है
Page 04 Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध	पूर्व राजदूतों ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर कोई प्रगति नहीं हुई
Page 06 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	डीआरडीओ ने चरण-2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया
Page 06 Syllabus : प्रारंभिक तथ्य	कच्छ के घास के मैदानों में अफ्रीका से चीते आने की संभावना
समाचार में शब्द	एंजल टैक्स
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: पाठ्यक्रम GS: 03 : भारतीय अर्थव्यवस्था	शहरी परिवर्तन रणनीतियों की रूपरेखा
मानचित्रण	विषय: भारत के राष्ट्रीय उद्यान

Page 04 : GS 2 : International Relations – Bilateral Relations

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश सचिव डेविड लैमी के साथ वार्ता के दौरान ब्रिटेन के साथ एफटीए को अंतिम रूप देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

- इस चर्चा में व्यापक रणनीतिक साझेदारी, प्रौद्योगिकी सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, साथ ही भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव और आर्थिक महत्व को भी स्वीकार किया गया।

India committed to FTA with the U.K., says Modi

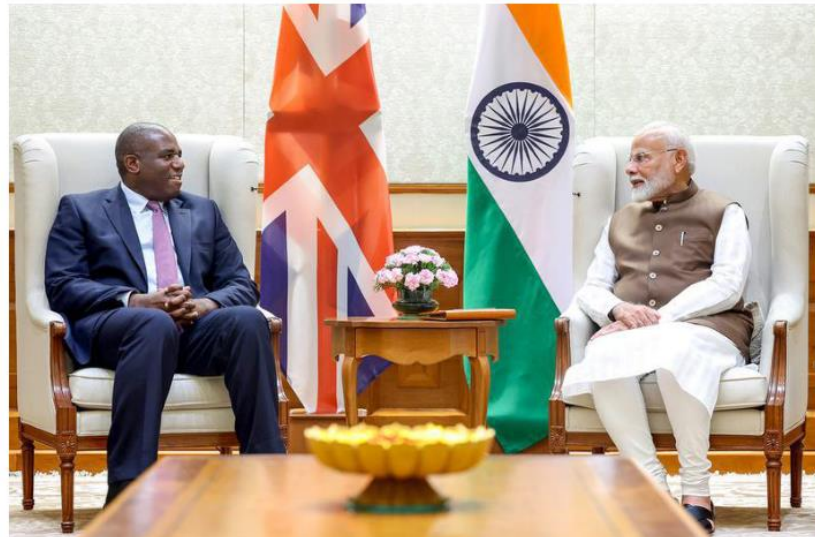
British Foreign Secretary David Lammy refers to 'unique living bridge' between the two countries, and says they are working together on climate action and creating opportunities for businesses

Kallol Bhattacharjee
NEW DELHI

India is committed to concluding a Free Trade Agreement with the United Kingdom, said Prime Minister Narendra Modi on Wednesday, after meeting the visiting Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs David Lammy – the highest ranking official from the United Kingdom to visit India since the Labour government won a landslide victory in the recent election.

"[I] appreciate the priority accorded by PM Keir Starmer to broaden and deepen the Comprehensive Strategic Partnership. Remain committed to elevating the ties. Welcome the bilateral Technology Security Initiative and the desire to conclude a mutually beneficial FTA," Mr. Modi said.

Mr. Lammy was hosted by External Affairs Minister S. Jaishankar for a round of talks where the two sides exchanged ideas on a wide range of issues. Mr. Jaishankar said the two sides should cooperate on "global matters on global plat-



Strengthening ties: Prime Minister Narendra Modi in a meeting with U.K. Foreign Secretary David Lammy, in New Delhi on Wednesday. ANI/@NARENDRAMODI/X

forms", indicating that India is seeking collaboration with the U.K. to deal with globally relevant issues like climate action.

"We are both countries which have a big global presence in different ways. So I think it's also important India and the U.K. work together on global issues and in global platforms," said Mr. Jaishankar.

After meeting Mr. Modi, Mr. Lammy referred to the

"unique living bridge" that connects India with the United Kingdom and said the two sides are building on "climate action while creating opportunities for British and Indian businesses". India and the U.K. have been discussing the FTA for several years now and have been caught up in a protracted negotiation.

"I am travelling to India in my first month as Fo-

reign Secretary because resetting our relationship with the Global South is a key part of how this government will reconnect Britain for our security and prosperity at home," Mr. Lammy had said in a statement ahead of his departure, calling India the "emerging superpower of the 21st century", one of the fastest growing economies, with the world's largest population.

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) क्या है?

- ✚ FTA, व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से आपसी बातचीत के माध्यम से व्यापार बाधाओं को कम करने या समाप्त करने के लिए देशों या क्षेत्रीय ब्लॉकों के बीच एक समझौता है।
- ✚ इसमें माल, सेवाएँ, निवेश, बौद्धिक संपदा, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।
- ✚ मुक्त व्यापार की यह अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद के विपरीत है।
- ✚ FTA को तरजीही व्यापार समझौते, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

भारत-यूके FTA का संभावित महत्व:

- ✚ महत्व: आर्थिक विकास: FTA द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, भारतीय और यूके व्यवसायों के लिए नए बाजार खोल सकता है, जिससे दोनों देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- ✚ नौकरी सृजन: व्यापार के बढ़े हुए अवसरों से विनिर्माण, सेवाओं और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन हो सकता है।
- ✚ निवेश प्रवाह: निवेशकों का बढ़ता विश्वास और कम व्यापार बाधाएँ दोनों देशों के बीच अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

भारत-यूके FTA का संभावित महत्व:

- ✚ महत्व: आर्थिक विकास: FTA द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारतीय और यूके व्यवसायों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं, जिससे दोनों देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- ✚ रोजगार सृजन: व्यापार के बेहतर अवसरों से विनिर्माण, सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन हो सकता है।
- ✚ निवेश प्रवाह: निवेशकों का बढ़ता विश्वास और व्यापार बाधाओं में कमी से दोनों देशों के बीच अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा मिल सकता है।
- ✚ बाजार पहुंच: भारतीय निर्यातक यूके के बाजार तक अधिक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जबकि यूके की कंपनियां भारतीय बाजार में अधिक आसानी से प्रवेश कर सकती हैं।
- ✚ नियामक सहयोग: मानकों और विनियमों का सामंजस्य व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है, लागत कम कर सकता है और दक्षता बढ़ा सकता है।
- ✚ रणनीतिक भागीदारी: आर्थिक संबंधों को मजबूत करने से भू-राजनीतिक संबंध भी बढ़ सकते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर अधिक सहयोग हो सकता है।
- ✚ उपभोक्ता लाभ: दोनों देशों के उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं की अधिक विविधता का आनंद ले सकते हैं।

चुनौतियाँ:

- ✚ नियामक मतभेद: भारत और यूके के बीच भिन्न मानक और विनियमन व्यापार वार्ता और कार्यान्वयन को जटिल बना सकते हैं।
- ✚ टैरिफ बाधाएँ: संवेदनशील वस्तुओं और सेवाओं पर पारस्परिक रूप से स्वीकार्य टैरिफ कटौती पर बातचीत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- ✚ गैर-टैरिफ बाधाएँ: सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और आयात कोटा जैसी गैर-टैरिफ बाधाओं को संबोधित करना मुश्किल हो सकता है।
- ✚ बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर): दोनों देशों के उद्योगों को संतुष्ट करने के लिए आईपीआर सुरक्षा को संरक्षित करना विवादास्पद हो सकता है।
- ✚ श्रम और पर्यावरण मानक: श्रम कानूनों और पर्यावरण विनियमों में मतभेदों को सुलझाना विवाद का विषय हो सकता है।

- ✦ कृषि क्षेत्र: बाजार खोलते समय घरेलू कृषि हितों की रक्षा करना दोनों देशों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा हो सकता है।
- ✦ जनमत: व्यवसायों और श्रमिक संघों सहित घरेलू हितधारकों से समर्थन प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- ✦ सेवा क्षेत्र की चिंताएँ: पेशेवरों की आवाजाही और सेवा क्षेत्र के विनियमों को संबोधित करना जटिल हो सकता है।
- ✦ राजनीतिक इच्छाशक्ति: बदलती सरकारों और प्राथमिकताओं के बीच राजनीतिक प्रतिबद्धता को बनाए रखना बातचीत की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

UPSC Prelims PYQ : 2017

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने WTO के व्यापार सुविधा समझौते (TFA) की पुष्टि की है
2. TFA, WTO के 2013 के बाली मंत्रिस्तरीय पैकेज का एक हिस्सा है
3. TFA जनवरी 2016 में लागू हुआ

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

उत्तर: a)

Page 04 : GS 2 : International Relations

लगातार वकालत के बावजूद, यूएनएससी सुधार और विस्तार के लिए भारत के प्रयास ठप हो गए हैं। भविष्य के यूएन शिखर सम्मेलन से पहले निराशा बढ़ रही है, भारत और जी-4 भागीदार स्थायी सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं।

- ✚ पारदर्शी बातचीत जारी है, लेकिन पर्याप्त प्रगति अभी भी मायावी बनी हुई है, जो मौजूदा बहुपक्षीय प्रणाली के साथ वैश्विक असंतोष को रेखांकित करती है।

No progress on UN Security Council expansion, say former Ambassadors

Suhasini Haidar
NEW DELHI

Despite consistent efforts by India and other countries, the move for United Nations Security Council (UNSC) reform and expansion has made “no progress” so far, conceded two former Indian Ambassadors to the United Nations, stressing that India must, however, continue to push its demand for inclusion in the top global decision-making body.

The lack of progress has been the subject of considerable frustration ahead of this year’s Summit of the Future at the UN (September 22-23) that is expected to bring in more than 150 world leaders to discuss plans to “reboot” the UN, with India and its partners in the G-4 (Brazil, Germany



Since 2023, there has only been movement in making the Inter-Governmental Negotiations process on UN reforms transparent

RUCHIRA KHAMBOJ
Former Indian Ambassador to UN

and Japan), all of whom claim a permanent seat at the UNSC, lashing out in recent statements about the proposed “Pact of the Future” that will be released.

“The short answer to whether there is progress in concrete terms, is no,” said India’s former Permanent Representative to the UN Ruchira Khamboj (2022-2024), who retired at the end of June, at a seminar organised at the India International Centre (IIC)

in Delhi. She added that since 2023, there has only been movement in making the Inter-Governmental Negotiations (IGN) process on UN reforms more transparent.

“You now have a live broadcast of the Inter-Governmental Negotiations. This wasn’t the case until last year, and there’s also a digital repository where you can put your proposals, and India’s proposals are very much there on ex-

pansion and reforms on their website, but in terms of real progress, let’s be very honest... the answer is no,” Ms. Khamboj said.

Last week, India’s Acting Permanent Representative R. Ravindra delivered a sharp address during an open debate at the UNSC, blaming the failure of the multilateral system on the “1945-vintage binary outlook reflected clearly in the composition of the Security Council”, referring to the fact that the five permanent members of the Security Council, or P5, are still those who are considered “victors” of the Second World War.

“Disillusionment with the existing multilateral system has led member states to consider various alternatives,” Mr. Ravindra said.

यूएनएससी सुधार पर प्रगति का अभाव:

- ✚ कोई ठोस प्रगति नहीं:

- निरंतर प्रयासों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के सुधार और विस्तार पर "कोई प्रगति" नहीं हुई है।
- भारत और अन्य देश, विशेष रूप से जी-4 (ब्राजील, जर्मनी, जापान), स्थायी सीटों के लिए दबाव बनाना जारी रखते हैं, लेकिन सुधार प्रक्रिया में ठहराव का सामना कर रहे हैं।
- ✚ **पूर्व भारतीय राजनयिकों के बयान:**
 - यूएन में भारत की पूर्व स्थायी प्रतिनिधि (2022-2024) रुचिरा खंबोज ने सुधार प्रयासों में ठहराव को उजागर किया।
 - जबकि अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, जैसे कि लाइव प्रसारण और प्रस्तावों के लिए डिजिटल रिपोर्टिंग, यूएनएससी विस्तार पर वास्तविक प्रगति अनुपस्थित है।
- ✚ **मोहभंग और विकल्प:**
 - मौजूदा बहुपक्षीय प्रणाली से मोहभंग के कारण सदस्य देश विभिन्न विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, जो मौजूदा यूएनएससी संरचना की प्रभावशीलता पर सवाल उठा रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:

- ✚ **गठन और उद्देश्य:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है, जिसकी स्थापना 1945 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यूएन चार्टर के तहत की गई थी।
- ✚ **सदस्यता:** इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य (पी5) शामिल हैं - चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका - और 10 निर्वाचित गैर-स्थायी सदस्य हैं जिन्हें महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
- ✚ **जिम्मेदारी:** यूएनएससी शांति के लिए खतरों को संबोधित करने, प्रतिबंधों को लागू करने और बल के उपयोग को अधिकृत करने के लिए जिम्मेदार है। यह शांति अभियान स्थापित कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है या सैन्य कार्रवाई को अधिकृत कर सकता है।
- ✚ **निर्णय लेना:** प्रस्तावों को 15 सदस्यों के नौ वोटों की आवश्यकता होती है, जिसमें पी5 की सर्वसम्मति भी शामिल है। स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है, जिससे उनमें से कोई भी प्रस्तावों को अवरुद्ध कर सकता है।
- ✚ **बैठकें और रिपोर्टिंग:** यूएनएससी नियमित रूप से मिलती है और आपातकालीन सत्रों के लिए बुलाई जा सकती है। यह अपनी गतिविधियों पर सालाना महासभा को रिपोर्ट करता है।

निष्कर्ष

- ✚ समकालीन संकटों से निपटने और उभरती चुनौतियों के अनुकूल ढलने के लिए संयुक्त राष्ट्र एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। जबकि सुधार की आवश्यकता स्पष्ट है, वैश्विक शासन, मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन में संयुक्त राष्ट्र की निरंतर भूमिका इसके स्थायी महत्व को दर्शाती है।
- ✚ जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक मुद्दों से जूझ रहा है, संयुक्त राष्ट्र मानवता की बेहतरी के लिए सहयोग, संवाद और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देने में सक्षम एक आवश्यक संस्था के रूप में खड़ा है।

UPSC Prelims PYQ : 2022

प्रश्न: "संयुक्त राष्ट्र साख समिति" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा गठित एक समिति है और इसकी देखरेख में काम करती है।
 2. यह परंपरागत रूप से हर साल मार्च, जून और सितंबर में मिलती है।
 3. यह अनुमोदन के लिए महासभा को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की साख का आकलन करती है।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- a) केवल 3
- b) 1 और 3
- c) 2 और 3
- d) 1 और 2

उत्तर: (a)

Page 06 : Prelims Fact

डीआरडीओ ने अपने चरण-II बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो 5,000 किलोमीटर तक की दूरी तक की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है।

INBRIEF**DRDO tests Phase-II ballistic missile defence system**

The DRDO on Wednesday successfully flight-tested the Phase-II Ballistic Missile Defence (BMD) system demonstrating the indigenous capability to defend against ballistic missiles of 5,000-km class. Phase 1 of the BMD, which can intercept ballistic missiles with a range of 2,000 km, has already been deployed. The maiden test of the Phase-II BMD was carried out in November 2022. "The Target Missile was launched from LC-IV Dhamra at 1620 hrs mimicking adversary ballistic missile, which was detected by weapon system radars deployed on land and sea and activated the Air Defence (AD) interceptor system," DRDO said in a statement.

- परीक्षण ने 5,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता का प्रदर्शन किया।
- चरण-I BMD, जो 2,000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों को रोकती है, पहले से ही तैनात है।
- चरण-II BMD का पहला परीक्षण नवंबर 2022 में किया गया था।
- परीक्षण के दौरान, एक लक्ष्य मिसाइल को LC-IV धामरा से 1620 बजे लॉन्च किया गया ताकि एक विरोधी बैलिस्टिक मिसाइल का अनुकरण किया जा सके।

- भूमि और समुद्र पर हथियार प्रणाली रडार ने लक्ष्य मिसाइल का पता लगाया।
- लक्ष्य को संलग्न करने के लिए वायु रक्षा इंटरसेप्टर प्रणाली को सक्रिय किया गया।

बैलिस्टिक मिसाइल

- यह एक रॉकेट-चालित स्व-निर्देशित रणनीतिक-हथियार प्रणाली है जो अपने प्रक्षेपण स्थल से एक पूर्व निर्धारित निश्चित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए एक परवल्यिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती है।
- बैलिस्टिक मिसाइलें पारंपरिक उच्च विस्फोटकों के साथ-साथ रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियार भी ले जा सकती हैं।

भारत में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली

- बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली (BMD) एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करती है।
- भारत का BMD विकास 1999 में कारगिल युद्ध के बाद शुरू हुआ।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य पाकिस्तान से संभावित परमाणु हमले के खिलाफ भारत की रक्षा को बढ़ाना था।
- भारत एक कार्यात्मक 'आयरन डोम' बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) तैनात करना चाहता है, जिसमें कम ऊंचाई और उच्च ऊंचाई दोनों तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हों।
- भारत का BMD मुख्य रूप से DRDO द्वारा BEL, एस्ट्रा माइक्रोवेव, L&T आदि जैसी कई सार्वजनिक और निजी फर्मों की मदद से विकसित किया गया है।
- भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें: अग्नि, K-4 (SLBM), प्रहार, धनुष, पृथ्वी और त्रिशूल।

UPSC Prelims PYQ : 2023

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

- बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी पूरी लड़ाई के दौरान सबसोनिक गति से जेट-प्रोपेल्ल्ड होती हैं, जबकि क्रूज मिसाइलें लड़ाई के शुरुआती चरण में ही रॉकेट-संचालित होती हैं।
- अग्नि-V एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस एक ठोस ईंधन वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d)

Page 06 : Prelims Fact

प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में, कुछ चीतों को गुजरात के बन्नी में एक नए प्रजनन केंद्र में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें गांधी सागर को प्राथमिकता दी जाएगी।

✚ बन्नी में पर्याप्त जगह है, लेकिन शिकार की उपलब्धता चिंता का विषय है। कुनो में चीतों को अक्टूबर में छोड़ने की तैयारी है, भविष्य में आयात की योजना है।

Grasslands in Kutch likely to host cheetahs from Africa

While the Gandhi Sagar sanctuary in Madhya Pradesh is the preferred location for the next lot of imports, Banni in Gujarat is also getting readied to house some of the big cats to land in India

Jacob Koshy
NEW DELHI

Some of the next batch of cheetahs being brought in from Africa, as part of the next phase of Project Cheetah, may be sent to a cheetah-breeding and conservation centre being built in the sprawling grasslands of Banni in the Rann of Kutch in Gujarat, senior officials in the Environment Ministry told *The Hindu*.

While the Gandhi Sagar sanctuary in Madhya Pradesh is the preferred location for the next lot of wild cats, with Banni being considered a potential habitat for over a decade, officials say there is a surge in activity to set up basic infrastructure in Banni and get it ready this year.

"The next [lot of] animals will go to Gandhi Sagar. However, the Gujarat government is setting up suitable enclosures in Banni where cheetahs can be bred. If all goes to plan, there is no reason (the site) cannot be readied in the next six months and some animals sent there," an official told *The Hindu*.

Banni is a vast grassland in the southern part of Kutch and extends to near-



Banni is a vast grassland in the southern part of Kutch and extends to nearly 3,500 sq.km. VIJAY SONEJI

ly 3,500 square kilometres. While that is plenty of space, more than that available in Kuno and Gandhi Sagar, there is barely enough prey to sustain a viable population.

Antelope species such as chinkara and blackbuck – the prey for the cheetah – are present in the Banni landscape but not enough for the big cat. "It will take years for enough prey, and practically this means chital – the main prey for the cheetahs in India – needs to be brought into these grasslands. There isn't an official plan yet but it is a site that is under consideration," the official added.

While the Madhya Pradesh Forest Department is tasked with managing the

cheetahs at Kuno in Madhya Pradesh, an expert steering committee gives scientific input on managing the programme. This includes recommending future sites for introducing fresh batches of cheetahs at regular intervals.

Of the 20 adult cheetahs brought to Kuno since September 2022, 13 survive. Additionally there are 13 cubs, making it 26 animals overall. However, the maximum capacity (in terms of available prey) of the Kuno reserve is for 21 adult animals.

The government's estimate is that India will need to import anywhere between 10 and 12 adult cheetahs every year for the next five years to groom a sus-

tainable breeding population. "One attractive aspect of Banni is that there are no leopards. So with enough prey, we can overtime sustain a larger population. But this is a long-term plan," an official said.

In October, all of the cheetahs in Kuno are expected to be released into the wild. Currently, most of them are in the bomas, or large enclosures that are a kilometre wide and long. These animals were brought in after infections and acclimatisation problems led to fatalities. Following the release of all the animals into the wild, preparations for the next batch are expected to begin – again from South Africa and Namibia.

✚ अगले बैच के कुछ चीतों को गुजरात के बन्नी में एक नए संरक्षण केंद्र में भेजा जा सकता है, जो प्रोजेक्ट चीता के अगले चरण का हिस्सा है।

- ✚ मध्य प्रदेश में गांधी सागर वर्तमान में चीतों के अगले समूह के लिए पसंदीदा स्थान है।
- ✚ गुजरात सरकार आवश्यक बुनियादी ढाँचा स्थापित करके बन्नी को तैयार करने के लिए काम कर रही है, जिसका लक्ष्य यदि संभव हो तो छह महीने के भीतर इसे पूरा करना है।
- ✚ लगभग 3,500 वर्ग किलोमीटर में फैले बन्नी में पर्याप्त जगह है, लेकिन चीतों की व्यवहार्य आबादी का समर्थन करने के लिए पर्याप्त शिकार की कमी है।
- ✚ चिंकारा और ब्लैकबक जैसी मृग प्रजातियाँ मौजूद हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में नहीं हैं; एक स्थायी शिकार आधार सुनिश्चित करने के लिए चीतल को पेश करने की आवश्यकता हो सकती है।
- ✚ कुनो में, सितंबर 2022 से 20 चीते लाए गए, जिनमें से 13 जीवित हैं और 13 शावक पैदा हुए हैं, कुल मिलाकर 26 जानवर हैं। रिजर्व की क्षमता 21 वयस्कों की है।

UPSC Prelims PYQ : 2012

प्रश्न: निम्नलिखित पर विचार करें:

1. काली गर्दन वाला सारस
 2. चीता
 3. उड़ने वाली गिलहरी
 4. हिम तेंदुआ
- उपर्युक्त में से कौन-से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं?
- a) केवल 1, 2 और 3
 - b) केवल 1, 3 और 4
 - c) केवल 2 और 4
 - d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: b)

Term In News : Angel Tax

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए निवेशकों के सभी वर्गों के लिए 'एंजेल टैक्स' को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा।



एंजल टैक्स के बारे में:

- ✦ यह गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा शेयर जारी करके जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाता था, अगर जारी किए गए शेयरों की कीमत कंपनी के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखी जाती है।
- ✦ उचित मूल्य से अधिक कीमत पर जुटाई गई अतिरिक्त धनराशि को आय माना जाता है, जिस पर कर लगाया जाता है।
- ✦ इसकी उत्पत्ति आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56(2) (viiB) से हुई है।
- ✦ शेयर बिक्री के माध्यम से काले धन की लूट को रोकने के लिए इसे पहली बार 2012 में पेश किया गया था।
- ✦ यह उचित बाजार मूल्य से अधिक शुद्ध निवेश पर 30.9% की दर से लगाया जाता था।
- ✦ 2019 में, सरकार ने कुछ शर्तों को पूरा करने पर स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स से छूट की घोषणा की। ये हैं:
 - स्टार्टअप को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा पात्र स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
 - स्टार्टअप की चुकता शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम की कुल राशि ₹25 करोड़ से अधिक नहीं हो सकती। इस राशि में अनिवासी भारतीयों (NRI), वेंचर कैपिटल फर्मों और निर्दिष्ट कंपनियों से जुटाई गई राशि शामिल नहीं है।
 - एंजेल निवेशकों के लिए, उचित बाजार मूल्य से अधिक निवेश की राशि पर 100% कर छूट का दावा किया जा सकता है।
 - हालांकि, निवेशक के पास पिछले 3 वित्तीय वर्षों में ₹2 करोड़ की कुल संपत्ति या ₹25 लाख से अधिक की आय होनी चाहिए।

UPSC Prelims PYQ : 2020

प्रश्न: भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के साथ पंजीकृत स्टार्ट-अप को शर्तों के साथ "एंजेल टैक्स" के भुगतान से छूट दी गई है। यह कर निम्न से संबंधित है:

- शेयर जारी करके नई सूचीबद्ध स्टार्ट-अप कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर देय कर, जहां शेयर की कीमत बेचे गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखी जाती है।
- वह कर जो स्टार्ट-अप को चुकाना होता है यदि उन्हें उच्च सफलता अनुपात के कारण ब्याज की रियायती दर पर ऋण मिलता है।
- शेयर जारी करके गैर-सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर देय कर, जहां शेयर की कीमत बेचे गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक देखी जाती है।
- वह कर जो स्टार्ट-अप को तब चुकाना होता है जब उनकी वार्षिक आय उनके उचित बाजार मूल्यांकन के अनुसार निर्दिष्ट सीमा को पार कर जाती है।

उत्तर: c)

An outlining of urban transformation strategies

Cities are home to about 50 crore people, accounting for about 36% of India's population. The urban population has been growing at a steady pace of 2% to 2.5% annually. The ever-growing pace of urbanisation in India calls for sustained investments, with a vision and determination. The maiden Budget of the new government has recognised cities as the growth hubs and offered many options and opportunities for the planned development and the growth of cities.



Sudhir Krishna

former Secretary,
Urban Development,
Government of India

The issue of housing

The Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) has been under implementation since 2015 and has provided as many as 85 lakh housing units for the Economically Weaker Sections (EWS)-Middle Income Groups (MIG) categories of population, with an investment of about ₹8 lakh crore. Of this, a quarter has been provided by the central government and the remaining by the beneficiaries and State governments. The Budget has proposed to give a further push to the scheme by announcing support for the construction of another one crore such units in urban areas with an investment of ₹10 lakh crore, which will include central assistance of ₹2.2 lakh crore in the next five years, against which ₹30,171 crore has been provided in the Budget for the current year. A part of this allocation will be available to provide interest subsidy to facilitate loans at affordable rates.

The migrant population working in industries has been surviving in general in slums and yearning for a roof over their heads and a functional housing unit close to their workplaces. The Budget has announced new rental housing with dormitory-type accommodation for industrial workers. This is envisaged to be developed in public-private partnership (PPP) mode with upfront financial support under the Viability Gap Funding (VGF) scheme. This is to the extent of 20% from the central government, with the possibility of similar support from the State government.

The core infrastructure requirement for cities includes water supply, sanitation, roads and sewerage systems. Specific to the cities, the Atal

Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) provides ₹8,000 crore, which, by itself, may not appear to be very substantial. However, the Finance Minister has announced the availability of the VGF window, provided that the project is taken up as a commercial venture in PPP Mode. Most cities have, over the years, got exposed to the PPP model, and it should be possible to speed up the development of such core infrastructure, where it is unavailable and upgrade it where it exists but is inadequate.

The Budget Speech also mentions a huge investment of ₹11.11 lakh crore for capex in infrastructure. While this would include highways and many other sectors, cities can also make efforts to partake a share in it. Similarly, a provision of ₹1.50 lakh crore is made available to States as an interest-free loan for infrastructure development. States could use this window also, for cities.

The Smart Cities Mission, that was launched in 2015, was provided budgetary support of ₹8,000 crore in 2023-24, which has been scaled down to ₹2,400 crore in 2024-25, to take care of the remnant commitments. However, a new window, the National Urban Digital Mission (NUDM), has been opened in this Budget, with a provision of ₹1,150 crore, with a focus on the digitisation of property and tax records and their management, with GIS mapping. These will help urban local bodies in managing their finances better, and also help property owners.

On city planning

The Budget has declared the intention of focusing on the planned development of cities. Municipalities would get the normal 'Finance Commission Grant' of ₹25,653 crore. In addition, a provision of ₹500 crore has been made for the incubation of new cities. With the development of mass rapid transit systems, cities can embark on transit-oriented development, wherein transit hubs can be surrounded by denser development without creating a traffic overload on roads. Moreover, a well-designed mobility plan can conveniently connect cities with their peri-urban areas and 'new cities'. Accordingly, the Budget

has announced an enhanced focus on economic and transit planning, with the orderly development of peri-urban areas utilising town planning schemes. The Budget has also proposed encouraging electric bus systems for cities and has provided ₹1,300 crore for it. E-buses offer an economical and eco-friendly operating system, but the main challenge is their higher upfront cost. However, with this budgetary support, it should get going.

Solid waste management

Solid waste management (SWM) is perhaps the biggest challenge that most cities face today. The Budget has announced a special thrust to introduce bankable projects for SWM in collaboration with State government and financial institutions. States and municipalities can also make use of the VGF for this purpose. Cities such as Indore, Madhya Pradesh, have shown the way in making SWM a financially viable proposition.

The Street Vendors Act, 2014, was enacted by Parliament to regulate street vendors in public areas and protect their rights. It also envisaged the preparation of street-vending plans and the creation of street-vending zones, with a view to make street-vending a healthy and safe option for consumers and vendors. The Budget has proposed to develop 100 weekly 'haats' or street food hubs in select cities. Perhaps States need not feel constrained with the number and can facilitate all cities in preparing street-vending plans and developing street vending 'haats' in various parts of the city, according to felt needs.

While the Budget has made a slew of provisions, financial as well as procedural, to push for planned urbanisation, cities, represented by the municipalities, and guided by the respective State governments, will have to show the vision and the determination to incorporate all the resources coming not only from the Union Budget but also augmented by their own resources.

Above all, the participation of citizens would remain the bedrock for the success of any city's development strategy.

The views expressed are personal

GS Paper 03 : भारतीय अर्थव्यवस्था - बुनियादी ढांचा

PYQ : (UPSC CSE (M) GS-3 2016): पूंजीगत बजट और राजस्व बजट के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन दोनों बजटों के घटकों की व्याख्या करें।

Mains Practice Question : वित्त वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रमुख शहरी विकास उपायों पर चर्चा करें, तथा आवास, बुनियादी ढांचे और शहरी नियोजन के लिए उनके निहितार्थों पर प्रकाश डालें।(250 w/15m)

संदर्भ:

- ✚ वित्त वर्ष 2025 का बजट आवास, बुनियादी ढांचे और शहर नियोजन पर ध्यान केंद्रित करके शहरी विकास को रेखांकित करता है।
- ✚ यह आवास और बुनियादी ढांचे में नए निवेश का प्रस्ताव करता है, स्मार्ट सिटीज मिशन और डिजिटल शहरी प्रबंधन का समर्थन करता है, और ठोस अपशिष्ट और सड़क विक्रेता मुद्दों को संबोधित करता है।
- ✚ सफलता के लिए प्रभावी कार्यान्वयन और नागरिक सहभागिता महत्वपूर्ण है।

शहरी जनसंख्या वृद्धि और निवेश की आवश्यकता

- ✚ भारत की शहरी आबादी, लगभग 50 करोड़, कुल जनसंख्या का 36% है, जो सालाना 2% से 2.5% की दर से बढ़ रही है।
- ✚ वित्त वर्ष 2025 का बजट विकास केंद्रों के रूप में शहरों के महत्व को स्वीकार करता है और उनके विकास के लिए एकरणनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है।

आवास पहल

- ✚ प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2015 से प्रभावी है, जो ₹8 लाख करोड़ के निवेश के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और मध्यम आय समूहों (एमआईजी) के लिए 85 लाख आवास इकाइयाँ प्रदान करती है।
- ✚ बजट में ₹10 लाख करोड़ के कुल निवेश के साथ शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त एक करोड़ आवास इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव है।
- ✚ इस पहल के लिए केंद्रीय सहायता अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये होगी, जिसमें चालू वर्ष के लिए 30,171 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- ✚ औद्योगिक श्रमिकों के लिए नए किराये के आवास सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में विकसित किए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार से 20% की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) सहायता और राज्य सरकारों से संभावित मिलान सहायता शामिल होगी।

कोर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश

- ✚ शहरों के लिए कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कें और सीवरेज सिस्टम शामिल हैं।
- ✚ कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) 8,000 करोड़ रुपये प्रदान करता है, जिसमें पीपीपी मोड में शुरू की गई परियोजनाओं के लिए वीजीएफ विंडो उपलब्ध है।

- ✚ बजट में बुनियादी ढांचे सहित समग्र पूंजीगत व्यय के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1.50 लाख करोड़ रुपये राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान किए गए हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों को लाभ हो सकता है।

स्मार्ट सिटी मिशन और नई पहल

- ✚ स्मार्ट सिटी मिशन का बजट 2023-24 में ₹8,000 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹2,400 करोड़ हो गया है।
- ✚ हालाँकि, नया राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) शुरू किया गया है, जिसमें संपत्ति और कर रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और GIS मैपिंग के लिए ₹1,150 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे शहरी स्थानीय निकायों को बेहतर वित्तीय प्रबंधन में मदद मिलेगी।

शहर नियोजन और पारगमन विकास

- ✚ बजट में नियोजित शहर विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें वित्त आयोग द्वारा ₹25,653 करोड़ का अनुदान और नए शहरों के विकास के लिए ₹500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- ✚ आर्थिक और पारगमन नियोजन पर अधिक ध्यान दिया गया है, जिससे पारगमन केंद्रों के आसपास पारगमन-उन्मुख विकास को बढ़ावा मिलता है।
- ✚ सार्वजनिक परिवहन को अधिक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक बस प्रणालियों के लिए ₹1,300 करोड़ का वित्तपोषण प्रदान किया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)

- ✚ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उजागर किया गया है। बजट में राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से बैंक योग्य एसडब्ल्यूएम परियोजनाओं को विकसित करने के लिए विशेष उपाय पेश किए गए हैं, जहाँ लागू हो, वीजीएफ का उपयोग किया जाएगा। इंदौर, मध्य प्रदेश एसडब्ल्यूएम के सफल कार्यान्वयन का एक उदाहरण है।

स्ट्रीट वेंडर्स और सार्वजनिक स्थान

- ✚ बजट में स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता देने के लिए चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने का प्रस्ताव है, जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, 2014 पर आधारित है, जो स्ट्रीट वेंडिंग को नियंत्रित करता है और इसे विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित और व्यवहार्य विकल्प बनाने का लक्ष्य रखता है।

चुनौतियाँ और कार्रवाई का आह्वान

- ✚ बजट के प्रावधानों के बावजूद, राज्य सरकारों द्वारा निर्देशित शहरों और नगर पालिकाओं से संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करने का आह्वान किया गया है।
- ✚ शहरी विकास रणनीतियों की सफलता के लिए नागरिक भागीदारी आवश्यक है।

निष्कर्ष

- ✚ वित्त वर्ष 2025 का बजट शहरी विकास के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, जिसमें आवास, बुनियादी ढाँचा, शहर नियोजन और अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- ✚ इन पहलों की सफलता प्रभावी कार्यान्वयन, राज्य सरकारों के साथ सहयोग और सक्रिय नागरिक भागीदारी पर निर्भर करेगी।

बजट और संवैधानिक प्रावधान

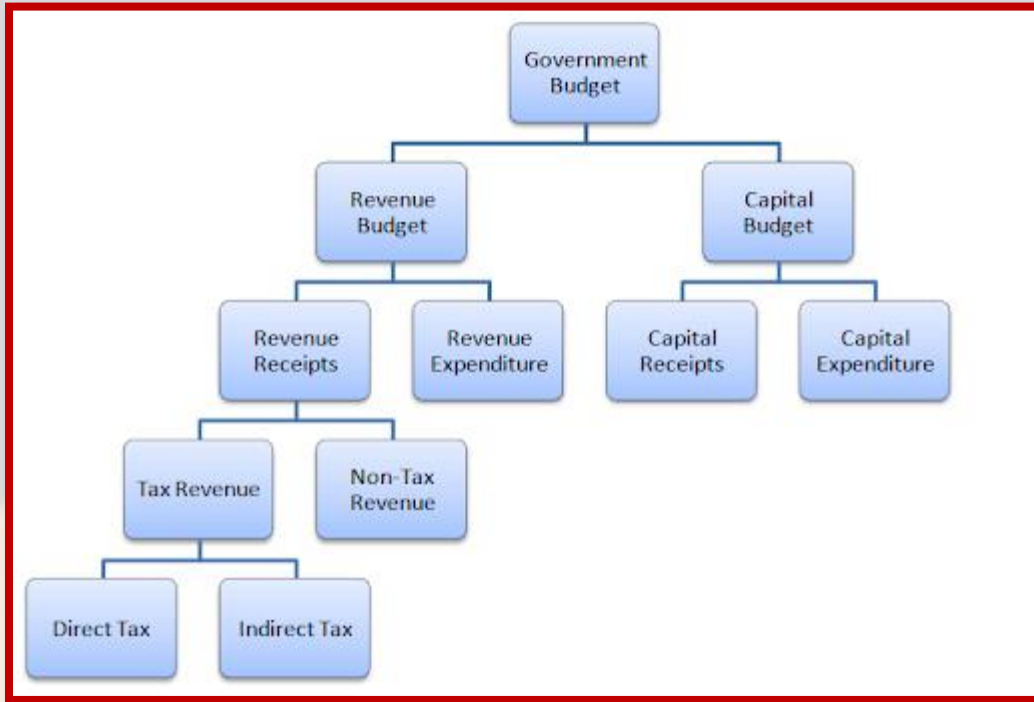
- ✚ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) कहा जाता है।
- ✚ यह एक वित्तीय वर्ष (जो चालू वर्ष के 01 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है) में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। इसके अलावा, बजट में शामिल हैं:
 - राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान,
 - राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन,
 - व्यय का अनुमान,
 - समापन वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण और उस वर्ष में किसी भी घाटे या अधिशेष के कारण, और
 - आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, यानी कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएँ, खर्च कार्यक्रम और नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरूआत।
- ✚ संसद में, बजट छह चरणों से गुजरता है:
 - बजट की प्रस्तुति।
 - सामान्य चर्चा।
 - विभागीय समितियों द्वारा जाँच।
 - अनुदानों की माँगों पर मतदान।
 - विनियोग विधेयक का पारित होना।
 - वित्त विधेयक का पारित होना।
- ✚ वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार नोडल निकाय है।

2017 में किए गए बदलाव

- ✚ बजट प्रस्तुति की तिथि को 1 फरवरी तक आगे बढ़ाना (पहले फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता था), रेलवे बजट का आम बजट में विलय, और योजना और गैर-योजना व्यय को समाप्त करना।
- ✚ मुख्य शब्द प्राप्तियाँ: यह सरकार द्वारा प्राप्त धन को दर्शाता है।

- ✚ इसमें शामिल हैं:
 - सरकार द्वारा अर्जित धन
 - राज्यों द्वारा उधार या ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त धन।
- ✚ योजना व्यय: नियोजन (यानी पंचवर्षीय योजनाएँ) के नाम पर किए गए सभी व्यय को योजना व्यय कहा जाता था। उदाहरण के लिए बिजली उत्पादन, सिंचाई और ग्रामीण विकास, सड़कों, पुलों, नहरों आदि के निर्माण पर व्यय।
- ✚ गैर-योजना व्यय: योजना व्यय के अलावा सभी व्यय गैर-योजना व्यय के रूप में जाने जाते थे। उदाहरण के लिए ब्याज भुगतान, पेंशन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को वैधानिक हस्तांतरण आदि।

सरकारी बजट के घटक



- ✚ **राजस्व बजट-** इसमें राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां शामिल हैं।
 - राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिनका सरकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें सरकार द्वारा कर (जैसे उत्पाद शुल्क, आयकर) और गैर-कर स्रोतों (जैसे लाभांश आय, लाभ, ब्याज प्राप्तियां) के माध्यम से अर्जित धन शामिल है।
 - राजस्व व्यय सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय है जो इसकी परिसंपत्तियों या देनदारियों को प्रभावित नहीं करता है। उदाहरण के लिए, इसमें वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।
- ✚ **पूंजीगत बजट-** इसमें पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल हैं।

- पूंजीगत प्राप्तियां उन प्राप्तियों को दर्शाती हैं जो सरकार की परिसंपत्तियों में कमी या देनदारियों में वृद्धि करती हैं। इसमें शामिल हैं: (i) सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों जैसी परिसंपत्तियों (या विनिवेश) को बेचकर अर्जित धन, और (ii) राज्यों द्वारा उधार या ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त धन।
- पूंजीगत व्यय का उपयोग परिसंपत्तियों को बनाने या देनदारियों को कम करने के लिए किया जाता है। इसमें शामिल हैं: (i) सरकार द्वारा सड़कों और अस्पतालों जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण पर दीर्घकालिक निवेश, और (ii) सरकार द्वारा राज्यों को ऋण के रूप में या अपने उधारों के पुनर्भुगतान के रूप में दिया गया धन।

बजट के अन्य प्रकार

- ✚ शून्य आधारित बजट: शून्य-आधारित बजट बनाने की एक विधि है जिसमें हर बार बजट बनाए जाने पर सभी खर्चों का मूल्यांकन किया जाता है और प्रत्येक नई अवधि के लिए खर्चों को उचित ठहराया जाना चाहिए।
- ✚ शून्य बजट शून्य आधार से शुरू होता है और सरकार के हर कार्य का उसकी ज़रूरतों और लागत के लिए विश्लेषण किया जाता है। फिर ज़रूरतों के आधार पर बजट बनाया जाता है।
- ✚ परिणाम बजट: परिणाम बजट प्रत्येक मंत्रालय और विभाग की प्रगति का विश्लेषण करता है और संबंधित मंत्रालय ने अपने बजट परिव्यय के साथ क्या किया है। यह सभी सरकारी कार्यक्रमों के विकास परिणामों को मापता है। इसे पहली बार वर्ष 2005 में पेश किया गया था।
- ✚ लिंग बजट: लिंग-बजट को "बजट के लिंग-आधारित मूल्यांकन, बजटीय प्रक्रिया के सभी स्तरों पर लिंग परिप्रेक्ष्य को शामिल करने और लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए राजस्व और व्यय का पुनर्गठन" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह वास्तव में लैंगिक समानता के लिए बजट है।
 - लैंगिक बजट के माध्यम से सरकार महिलाओं के लिए विकास, कल्याण, सशक्तिकरण योजनाओं और कार्यक्रमों पर खर्च की जाने वाली राशि की घोषणा करती है।

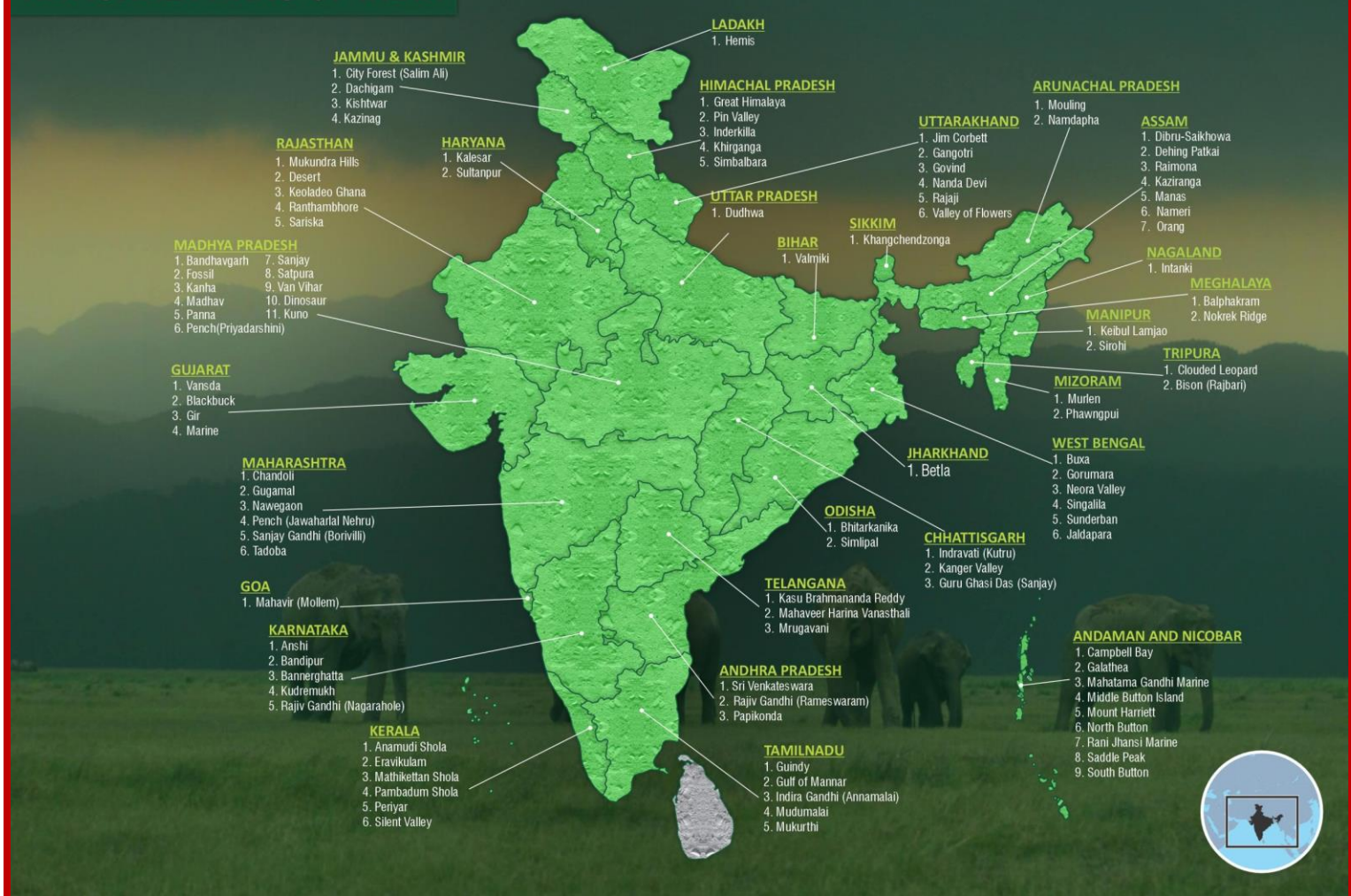
संतुलित, अधिशेष और घाटे वाला बजट

- ✚ संतुलित बजट - यदि अपेक्षित व्यय किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्याशित प्राप्तियों के बराबर है, तो सरकारी बजट को संतुलित माना जाता है।
- ✚ अधिशेष बजट - जब अपेक्षित राजस्व किसी विशेष व्यावसायिक वर्ष के लिए अनुमानित व्यय से अधिक हो, तो बजट को अधिशेष कहा जाता है। यहाँ, बजट अधिशेष हो जाता है, जब लगाए गए कर, व्यय से अधिक होते हैं।
- ✚ घाटा बजट - यदि व्यय किसी निर्दिष्ट वर्ष के राजस्व से अधिक हो तो बजट घाटे में होता है।

Mapping : National Parks of India

- ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए निर्धारित किया जाता है।
- एक राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध होते हैं।
- उनकी सीमाएँ निश्चित और परिभाषित होती हैं।
- एक राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और जैव विविधता संरक्षण करना है।

NATIONAL PARKS OF INDIA



राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर क्या अनुमति है और क्या नहीं:

- यहाँ, किसी भी मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं है।
- यहाँ पशुओं को चराने और निजी काश्तकारी अधिकारों की अनुमति नहीं है।

- ✚ वन्यजीव अधिनियम की अनुसूचियों में उल्लिखित प्रजातियों का शिकार या कब्जा करने की अनुमति नहीं है।
- ✚ कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान से किसी भी वन्यजीव को नष्ट, हटा या शोषण नहीं करेगा या किसी भी जंगली जानवर के आवास को नष्ट या नुकसान नहीं पहुँचाएगा या किसी भी जंगली जानवर को राष्ट्रीय उद्यान के भीतर उसके आवास से वंचित नहीं करेगा।
- ✚ उन्हें 'अभयारण्य' के दर्जे में नहीं बदला जा सकता।

राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा:

- ✚ राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा की जा सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- ✚ राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105
- ✚ कुल क्षेत्रफल 40,501 वर्ग किमी.
- ✚ अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान राज्य पी. (9), अंडमान और निकोबार (9)
- ✚ पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
- ✚ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान
- ✚ सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान
- ✚ नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कुनो राष्ट्रीय उद्यान

भारत में 104 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका क्षेत्रफल 43,716 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1.33% है

राज्यवार राष्ट्रीय उद्यानों की सूची

राज्य का नाम	संरक्षित क्षेत्र का नाम
आंध्र प्रदेश	पापिकोंडा
	राजीव गांधी (रामेश्वरम)

	श्री वेंकटेश्वर
अरुणाचल प्रदेश	मौलिंग नमदाफा
असम	डिब्रू-सैखोवा
	काजीरंगा
	मानस
	नामेरी
	राजीव गांधी (ओरंग)
	देहिंग पटकाई रायमोना
बिहार	वाल्मीकि
छत्तीसगढ़	गुरु घासीदास (संजय)
	इंद्रावती (कुटरू)
	कांगेर घाटी

